उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 17 | 1-15 सितंबर 2021 | ₹ 20/-

संघ प्रमुख की मुस्लिम नेताओं से चर्चा पर बहस

- ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक
- अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में मतभेद
- इजरायली प्रधानमंत्री का मिस्र दौरा
- मदरसों को सहायता देने पर सवाल

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

प्राक्कथन

सारांश 03

राष्ट्रीय

संघ प्रमुख की मुस्लिम नेताओं से चर्चा पर बहस 04
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक 10
उत्तर प्रदेश चुनाव हेतु ओवैसी की भागदौड़ 11
झारखंड विधान सभा में नमाज के लिए कमरा 14
सेक्युलरवादियों के निशाने पर संघ परिवार 15

विश्व

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में मतभेद 17
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला 20
यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान को दी करोड़ों की सहायता 20
मस्जिद में धमाके के आरोपी को 53 वर्ष की कैद 21
पाकिस्तान में अध्यापकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर प्रतिबंध 21

पश्चिम एशिया

इजरायली प्रधानमंत्री का मिस्र दौरा 22
हूतियों की गोलाबारी से सऊदी बंदरगाह को भारी नुकसान 22
ईरान वार्ता के लिए तैयार 23
सऊदी अरब में सिनेमाघर 24
इस्लामिक स्टेट के हमले में 13 इराकी पुलिसकर्मी मरे 24

अन्य

अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न संस्थानों में पदाधिकारी नियुक्त 25
मदरसों को सहायता देने पर सवाल 26
निकाह को आसान बनाने की मांग 27
वसीम रिजवी के खिलाफ याचिका खारिज 28
तब्लीगी मरकज को बंद रखा जाएगा 28

सारांश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने मुस्लिम समाज में संघ के बारे में फैली हुई गलतफहमियों को दूर करने के लिए वार्तालाप का जो सिलसिला शुरू किया था वह अब रंग ला रहा है। हाल ही में इस सिलसिले में मुंबई में मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक बैठक का आयोजन पुणे की एक संस्था द्वारा किया गया। इस बैठक में अनेक बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों के अतिरिक्त मुस्लिम उलेमाओं ने भी हिस्सा लिया। उर्दू समाचारपत्रों ने इस बैठक को काफी प्रमुखता से प्रकाशित किया है आर अनेक समाचारपत्रों ने उस पर संपादकीय भी लिखे हैं। सबसे खास बात यह है कि पहली बार अमीर-उल-हिंद मौलाना अरशद मदनी ने भी खुलकर मोहन भागवत के विचारों का समर्थन किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है। अरशद मदनी देवबंदी विचारधारा के मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरू और विचारक हैं। उर्दू समाचारपत्रों ने भी भागवत जी के प्रयासों की सराहना की है। हालांकि कुछ कट्टरपंथियों को यह सद्भावना के प्रयास पसंद नहीं आए हैं।

देश में संघ परिवार की बढ़ती हुई लोकप्रियता सेक्युलरवादियों और वामपंथियों को पसंद नहीं आ रही है। यही कारण है कि बहुचर्चित गीतकार जावेद अख्तर ने एक टीवी चैनल पर संघ की तुलना तालिबान से कर दी। उनके इस बयान का राष्ट्रवादियों द्वारा विरोध किया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि अगर जावेद अख्तर ने अपने इस बयान पर संघ परिवार से माफी नहीं मांगी तो उनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाएगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने भी जावेद अख्तर क बयान का समर्थन किया है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में कूदने की तैयारो कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक इन पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ उपेक्षित ही रखा है। उन्होंने कहा कि उनका एक मात्र लक्ष्य देश के मुसलमानों को राजनीति में उनकी उचित भागीदारी दिलाना है। औवैसी ने उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में 100 उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ान के लिए उन्होंने बहुचर्चित बाहुबलियों को भी साधने का अभियान तेज कर दिया है। अतीक अहमद और उनकी पत्नी मजलिस के सदस्य बन चुके हैं। कहा जाता है कि अब उनका अगला निशाना मुख्तार अंसारी हैं, जिन्हें बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी पार्टी का टिकट देने से इंकार कर दिया है। इन दिनों समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान भी अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। अगर मुख्तार अंसारी और आजम खान मजलिस का दामन थाम लेते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति एक नया मोड़ लेगी।

अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता की बागडोर तो संभाल ली है मगर मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही उनके विभिन्न गुटों के बीच मतभेद उत्पन्न होने शुरू हो गए हैं। कहा जाता है कि हाल ही में उप प्रधानमंत्री मल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी गुट के प्रमुख खलीलुर रहमान हक्कानी के बीच जोरदार झड़पें हुई हैं।

पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ बढ़ते हुए संबंध भारत के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के प्रमुख ने काबुल जाकर तालिबान के नेताओं के साथ लंबी बातचीत की है। पाकिस्तान के नापाक इरादों का संकेत इस बात से भी मिलता है कि तालिबान के राजनीतिक विंग के प्रवक्ता सुहैल साहीन ने घोषणा की है कि दुनिया भर में जहां भी मुसलमानों का उत्पीड़न होगा तालिबान उसका डटकर विरोध करेंगे। उन्होंने इस संदर्भ में कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में मुसलमानों के कथित उत्पीड़न का मामला भी उठाया है। ■

संघ प्रमुख की मुस्लिम नेताओं से चर्चा पर बहस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने देश के मुसलमानों में व्याप्त आरएसएस से संबंधित गलतफहमियों को दूर करने का जो अभियान शुरू किया है अब उसका मुस्लिम क्षेत्रों में जबर्दस्त स्वागत शुरू हो गया है।

इंकलाब (7 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के एक होटल में मुस्लिम प्रतिनिधियां से बैठक की। इसका आयोजन पुणे की एक संस्था 'ग्लोबल स्ट्रैटिजिक पॉलिसी फाउंडेशन' की ओर से किया गया था। इस तरह की बैठकें मुसलमानों में संघ के प्रति फैली हुई गलतफहमियों को दूर करने के लिए गत कई महीनों से देश के विभिन्न भागों में की जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोहन भागवत ने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों को मिलजुलकर रहना चाहिए और इसी दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। भारत में हमेशा से राष्ट्रीय एकता और सहअस्तित्व को बढ़ावा दिया जाता रहा है। यही कारण है कि आप विश्व के किसी भी हिस्से में चले जाएं इसी आधार पर आपकी इज्जत की जाती है। देश में किसी को किसी का डर नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान हिंदस्तान में हाशिए पर नहीं हैं बल्कि वे अपनी योग्यता के आधार पर उन्नति करके किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अनेकता में एकता ही इस देश की पहचान है और यही इस देश की संस्कृति में है। हम सबको इसकी पहचान को बरकरार रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि अफगानिस्तान में जो हुआ है उससे भारत को सावधान रहने की जरूरत है।

इंकलाब (8 सितंबर) के विशेष प्रतिनिधि ने मुंबई में आयोजित इस बैठक में भाग लेने के बाद कहा है कि मोहन भागवत ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर संघ के दृष्टिकोण में कोई कमी है और उसके बारे में हमें बताया जाता है तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक पुरानी परंपरा है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का शानदार भूतकाल जुड़ा हुआ है। इस देश का भविष्य भी इन दोनों के सौहार्द्रपूर्ण संबंधों पर निर्भर है। अंग्रेजों ने अपने फायदे के

लिए हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़वाया और इस तरह की साजिशें आज भी चल रही हैं। हमें हिंदू-मुसलमानों के वर्चस्व से कोई मतलब नहीं बल्कि हमारा लक्ष्य भारत का वर्चस्व है। श्री मोहन भागवत ने कहा कि अंग्रेजों ने मुसलमानों क दिमाग में यह बात डाली थी कि अगर हिंदुओं पर भरोसा करोगे तो दश से इस्लाम खत्म हो जाएगा। लेकिन सबने देखा कि इस्लाम हिंदुस्तान में पूरी तरह से मौजूद है। इसलिए मुसलमानों के समझदार नेतृत्व को कट्टरपंथी और अतिवादी विचारधारा का विरोध करना चाहिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि आरएसएस की हर बात का समर्थन किया जाए। अगर किसी बात पर मतभेद है तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। हिंदुत्व के बारे में लोगों को बहुत सी गलतफहमियां हैं जिनको दूर किया जाना जरूरी है।

गोष्ठी के संयोजक डॉ. अनंत भागवत ने 'ग्लोबल स्ट्रैटिजिक पॉलिसी फाउंडेशन' के कार्यक्रमों और लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2018 में इस फाउंडेशन की ओर से दिल्ली में कारगिल के शहीद मोहम्मद हनीफ की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अंजुमन इस्लाम के प्रमुख डॉ. जहीर काजी ने कहा कि हमारी संस्था में एक लाख दस हजार छात्र दीनो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इनमें महिलाओं की एक बड़ी संख्या शामिल है। इस बैठक में अल-कुरान एकेडमी, कैराना के प्रवर्तक मुफ्ती अतहर शम्सी, मुस्लिम विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी, इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी, डॉ. नदीम किरमानी, नफीस कुरैशी, मौलाना सलमान मोहम्मद, माहम्मद आसिफ शम्सी, ताहिर शम्सी और आदिल फारूक भी उपस्थित थे।

इंकलाब (9 सितंबर) के अनुसार बैठक में भाग लेने के बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कहा कि सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने मुस्लिम नेताओं के साथ वार्तालाप का जो सिलसिला शुरू किया है उसके परिणाम बहुत लाभदायक होंगे। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी से विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई है और सम्मेलन में जो भाषण हुए हैं उससे यह साफ होता है कि हिंदुओं और मुसलमानों में दूरियां खत्म होंगी, गलतफहमियों का अंत होगा और नजदीकियां बढ़ेंगी। मोहन भागवत के हिंदू-मुसलमान के डीएनए पर दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह बात तो कुरान ने हजारों वर्ष पूर्व फरमाई है कि हम सबको पैदा करने वाला एक रब है। जरूरत इस बात की है कि हम कुरान की बात को समझें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। इससे हालात बदलेंगे और हमारा देश एक बार फिर शांति और भाईचारे वाला देश कहलाएगा। कैराना स्थित अल कुरान एकेडमी के संस्थापक मुफ्ती अतहर शम्सी ने कहा कि नफरत की खेती इतनी बढ़ गई है कि इसको समाप्त करने में अभी समय लगेगा। उनकी अकेडमी की पूरी टीम इस बैठक में भाग लेने के लिए आई हुई थी और हमारा एक मात्र लक्ष्य यह है कि वार्ता शुरू हो। मोहन भागवत से मुलाकात का एक मात्र लक्ष्य यह है कि नफरतों की दीवार को तोड़ा जाए और दोस्ती का माहौल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हर चीज का फौरन नतीजा चाहते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे सब्र से काम लें। नफरत समाप्त करना और मोहब्बत पैदा करना निरंतर प्रयासों से ही संभव हो सकता है।

इंकलाब (9 सितंबर) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद के मौलाना मेहदी हसन ने मोहन भागवत की इस बात के लिए आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में इस्लाम आक्रांताओं द्वारा आया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को सच्चे इतिहास का ज्ञान नहीं है। उन्हें अंग्रेजों के गढ़े हुए इतिहास की बजाय सच पर आधारित इतिहास का अध्ययन करना चाहिए।

भारत में इस्लाम को सूफियों ने फैलाया और वे मुसलमान शासकों के यहां आने से पहले ही पहुंच चुका थे। किसी मुस्लिम शासक ने इस्लाम के प्रचार का कभी कोई प्रयास नहीं किया। देश में सबसे पहली मस्जिद केरल में है जा कि किसी मुस्लिम आक्रांता ने नहीं बल्कि अरब व्यापारियों और सूफियों ने पैगम्बर के जीवन काल में ही बना दी थी। उन्होंने भागवत के इस बयान की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। उन्होंने कहा कि यह झूठा प्रचार मुसलमानों को हिंदू सिद्ध करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

इंकलाब (11 सितंबर) के अनुसार इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि मोहन भागवत द्वारा हिंदू-मुस्लिम सद्भावना के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वह देश के हित में है। इससे देश मजबूत होगा।

अवधनामा (8 सितंबर) के अनुसार मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से अपील की ह कि वे कट्टरपंथियों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के लिए सबको मिलजुलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम अक्रांताओं के साथ आया यह इतिहास है और उसे इसी शक्ल में बताया जाना चाहिए। अतिवादियों के खिलाफ मुस्लिम समाज जितनी जल्दी खड़ा होगा उतना ही अच्छा है। उन्होनें कहा कि हिंदुस्तान बतौर सुपर पावर किसी को भयभीत करने के पक्ष में नहीं है। हिंदू शब्द हमारी मातभूमि, पूर्वजों और भारतीय संस्कृति की विरासत के खजाने की तरह है और हर हिंदुस्तानी हिंदू है। हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं।

अखबार-ए-मशरिक (9 सितंबर) के अनुसार अमीर उल-हिंद और विख्यात मुस्लिम नेता मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना पुराना दृष्टिकोण बदल रहा है और अब वह सही रास्ते पर है। 'दैनिक भास्कर' को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि इस देश में रहने वाले गुर्जर, जाट और राजपूतों की जातियां दोनों धर्मों में हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने देश से मोहब्बत है और तथाकथित आतंकवाद के आरोप में जो मुसलमान पकड़े जाते हैं उनमें अधिकांश को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। इसलिए वे ऊपरो अदालतों से बरी हो जाते हैं। मौलाना ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संगाम में मुसलमान उलेमाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 1857 में अंग्रेजों ने लालकिले से जामा मस्जिद तक 33 हजार मुस्लिम उलेमाओं को फांसी पर लटका दिया था। इसोलिए मौलाना कासिम ननोतवी, फजल रहमान उस्मानी और मोहम्मद आबिद ने दारूल उलूम देवबंद की आधारशिला रखी थी। इनका लक्ष्य मुजाहिद पैदा करना था। महिलाओं को मुजाहिद बनाने का लक्ष्य न पहले था न आज है। उन्होंने कहा कि हम इस बात के पक्ष में हैं कि महिलाएं पर्दे में रहें और इसलिए इस्लाम सह शिक्षा के खिलाफ है।

सियासत (8 सितंबर) के अनुसार दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूव अध्यक्ष जफरूल इस्लाम खान ने कहा है कि इस समय देश में जो हालात हैं उसको देखते हुए मोहन भागवत को मुसलमानों को सलाह देने की बजाय हिंदुओं को सलाह देना चाहिए जो खुलेआम भीड़तंत्र द्वारा मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं। मुसलमान शांत हैं और वे पूरे सब्र से काम ले रहे हैं। हिंदुओं का आतंकवाद तो जगजाहिर है। मगर उन्हें मनमानी करने की सरकार ने खूली छूट दे रखी है। इसलिए मोहन भागवत को पहले अपने हिंदू संगठनों को आतंकवाद और अतिवाद से दूर रहने का उपदेश देना चाहिए।

सियासत ने 8 सितंबर के संपादकीय में मोहन भागवत के मुंबई में दिए गए भाषण की

चर्चा करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि मोहन भागवत आरएसएस के पूर्ववर्ती नेताओं के विचारधाराओं से हटकर बात करते हैं। वे समय-समय पर देश के मुसलमानों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि भारत में उन्हें समान अवसर प्राप्त हैं। इसलिए उन्हें किसी तरह की शंकाओं का शिकार होने की जरूरत नहीं है। कभी वे अपने मूल मुद्दे से भटककर यह भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम लोग हिंदू हैं। क्योंकि उनकी नजर में हिंदू कोइ धर्म नहीं है बल्कि हमारे देश की संस्कृति है। वे कभी मुसलमानों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने वालों को चेतावनी देने का प्रयास करते हैं और स्वयं भी कभी-कभी मुसलमानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। आज देश में जा हालात पैदा हो गए हैं उनसे हिंदू-मुसलमान दो धर्मों में बांट दिए गए हैं। कोई कहता है कि यह हिंदू राष्ट्र है। मुसलमानों को यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई कहता है कि मुसलमानों को यहां से पाकिस्तान चले जाना चाहिए और ऐसे सभी तत्वों को संघ का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। मोहन भागवत ऐसे बयान देने वालों पर लगाम कसने की कोई कोशिश नहीं करते बल्कि संघ ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन देता है।

वैसे तो मोहन भागवत लगातार कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। उनका यह भी कहना था कि हिंदू राष्ट्र का यह मतलब नहीं है कि यहां मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। जिस दिन देश में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी उसी दिन हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। मगर यह सब सिर्फ बयानबाजी है। आज देश में हालात बिल्कुल विपरीत हैं। मुसलमानों के खिलाफ हर जगह जहर उगला जा रहा है। उन्हें नागरिक तक मानने से इंकार किया जा रहा है। उन्हें मतदान से वंचित करने की बात हो रही है। उन्हें पाकिस्तान चले जाने को कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर मोहन भागवत यह कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए भी जगह है। यह दरअसल मुसलमानों का बेवकूफ बनाने की कोशिश है। एक ओर तो उन्हें मीठे बोल से प्रसन्न किया जा रहा है। दूसरी ओर मामूली से बहाने की आड़ लेकर उन्हें सरेआम पीट-पीटकर मार दिया जाता है। ऐसे जुनूनी हत्यारों को संघ से संबंधित संगठनों का न सिर्फ समर्थन प्राप्त होता है बल्कि उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाता है। उन्हें अदालतों से रिहा करवाया जाता है और केन्द्रीय मंत्री तक उनका स्वागत करते हैं। जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है यह किसी के लिए संभव नहीं कि वह इस देश के सेक्युलर स्वरूप को बदल सके। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस संविधान का पालन करें।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 सितंबर) के अनुसार मोहन भागवत के मुंबई में दिए गए बयान की आलोचना करते हुए शकील रशीद ने संपादकीय में कहा है कि "मुसलमान स्वयं को हिंदू क्यों कहें? मेरा यह प्रश्न आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत से है, जिन्होंने 6 सितंबर को मुंबई में एक बैठक में वहां उपस्थित चंद मुसलमानों से कहा कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हैरानी की बात यह है कि उनके सामने जो भी मुसलमान बैठे हुए थे उनमें से किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि हम हिंदू नहीं हम तो मुसलमान हं। मैं किसी ऐसी मुलाकात का विरोधी नहीं हूं। जब जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई थी तो मैंने उसका स्वागत किया था। जब रामलाल के प्रयास पर अरशद मदनी दिल्ली के केशवकुंज में मोहन भागवत से मिलने गए थे तो इस मुलाकात की आलोचना करते हुए साजिद रशीदी ने कहा था कि मुस्लिम नौजवानों के साथ आरएसएस जो कुछ कर रहा है उसके बाद भी हम यह उम्मीद रखें कि वे हमारी बात मानकर शांति के लिए काम करेंगे और मुसलमानों को उनका संवैधानिक अधिकार देंगे यह केवल मुर्खता है।

जिस पार्टी की नींव ही मुस्लिम दुश्मनी पर हो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है।"

लेखक ने आगे कहा है कि मोहन भागवत ने मौलाना अरशद मदनी को सिर्फ इसलिए बुलाया था कि वे स्वयं को हिंदू कहना शुरू कर दें और समझदार मुसलमान के तौर पर मुसलमानों के कट्टरवाद की निंदा करें। अब मोहन भागवत ने मुंबई में इसी लक्ष्य से मुस्लिम विद्वानों, बुद्धिजीवियों और उद्योगपतियों को बुलाया था जो कि मुस्लिम समाज की क्रीम समझे जाते हैं। भागवत ने उनको बुलाकर आम मुसलमानों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैंने हाल हो में मोहन भागवत की एक पुस्तक 'भविष्य का भारत' पढ़ा था, जिसमें एक जगह वे लिखते हैं कि जो गोरक्षा की बात करते हैं वे भीड़ द्वारा लोगों को मारने वाले नहीं हैं बल्कि वे समाज में सुधार चाहते हैं और वे उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। एक अन्य जगह पर वे लिखते हैं, "पुरानी परंपराओं, राष्टवाद और अपने पूर्वजों की दृष्टि से हम सब हिंदू हैं। यह हमारा कहना है और इसे हम कहते रहेंगे। इन सब बातों का निष्कर्ष यह है कि मुसलमान अपने राष्ट्रवादी होने को सिद्ध करने के लिए स्वयं को हिंदू कहना शुरू कर दें। हिंदुस्तान, भारत या इंडिया के मुसलमान हिंदुस्तानी, भारतीय या इंडियन तो हो सकते हैं मगर वे हिंदू बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि हिंदू शब्द एक विशेष धर्म का सूचक है और वह धर्म मुसलमानों का धर्म नहीं है। साफ है कि भागवत की इन बातों को कोई मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि इस देश के मुसलमान स्वयं को हिंदू नहीं कह सकते। क्योंकि मुस्लिम और हिंदू अलग-अलग धर्म हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। अब अगर कोई मुसलमान भागवत की बात मानकर स्वयं को हिंदू कहने लगे तो उसका सीधा मतलब यह होगा कि वह मुसलमान नहीं है। साफ है कि भागवत का इरादा सारे मुसलमानां को हिंदू बनाना है।"

मुंबई में मोहन भागवत की बैठक पर टिप्पणी करते हुए **मुंबई उर्दू न्यूज** ने 8 अगस्त के अंक में कहा है कि शहर के एक पांच सितारा होटल में आरएसएस के चीफ ने मुट्ठी भर लोगों, जिनमें कुछ मुसलमान भी शामिल थे। इनमें आरिफ मोहम्मद खान और उन जैसे कुछ भगवावादी मुसलमान भी मौजूद थे। इस बैठक को मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मोहन भागवत की बैठक के रूप में प्रमोट किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम में आपस में कोई बातचीत नहीं हुई थी। सब श्रोताओं को मोहन भागवत का भाषण ही सुनना पड़ा। हिंदत्व के अतिवाद, हिंसा और दहशतगर्दी की देश में बढ़ती हुई वारदातों के कारण दुनिया भर में मोदी सरकार की जो बदनामी हो रही है और अल्पसंख्यकों पर हमलों को आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों को जिस तरह से देश और विदेश में आलोचना हो रही है उसका देखते हुए आरएसएस चीफ ने एक पब्लिक रिलेशन अभियान शुरू किया है। मुंबई में हुई यह बैठक इसी अभियान का एक हिस्सा है।

मुंबई में अपने भाषण में भागवत ने देश में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया बल्कि वे अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से ही बातचीत करते रहे। इनके भाषण से यह बात समझ में नहीं आती कि वे मुसलमानों के जख्म पर मरहम लगा रहे थे या नमक छिड़क रहे थे। या फिर वे स्वयं कन्फ्यूज हैं। आरएसएस समर्थक मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रिमंडल बनाया है। इस मंत्रिमंडल के दावे के अनुसार मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, यहूदी इत्यादि हिंदू नहीं है। इसके अतिरिक्त देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के काफी वर्ग ऐसे हैं जो स्वयं को हिंदू नहीं मानते। फिर मोहन भागवत सबका यह पाठ क्यों पढ़ाने आए हैं कि सभी हिंदू हैं? विदेशी

आक्रमणकारियों से इस्लाम को जोड़कर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए संघ प्रमुख की मुसलमानों से मुलाकातें और उनके भाषणबाजी को सिर्फ पब्लिक रिलेशन अभियान से ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 सितंबर) के अनुसार मोहन भागवत ने झारखंड में एक समारोह में भाषण देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया को तालिबान जैसे खतरों से निपटने के लिए रास्ता तलाश करना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज ने 7 सितंबर के संपादकीय में कहा है कि संघ मुख्यालय में पांच राज्यों के आने वाले चुनाव के बारे में जो रणनीति तैयार की गई थी मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मोहन भागवत की हुई बैठक उसी का एक हिस्सा है। हैरानी की बात यह है कि एक ओर तो आरएसएस यह चाहता है कि प्रत्येक मुसलमान तालिबान के विरोध में बयान जारी करे और दूसरी ओर स्वयं भारत सरकार तालिबान के साथ बातचीत कर रही है। दरअसल कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इसलिए तालिबान की आड़ लेकर संघ परिवार वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाहता है।

अवधनामा (14 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मुसलमानों को अछूत और घृणित समझने वाले संगठन के प्रमुख इधर कुछ दिनों से मुसलमानों से संपर्क बढ़ाने और उनसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी बहाने से कुछ मुसलमानों को सफल किया जाता है, उन्हें भाषण पिलाए जाते हैं। जबकि इन बैठकों में भाग लेने वाले कथित मुसलमानों का मुस्लिम समाज से कोई संबंध नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आरएसएस और मुसलमानों के बीच वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। यह जरूर होनी चाहिए। मगर उनका स्वरूप एकतरफा न हो बल्कि जिम्मवार और प्रमुख मुस्लिम नेता मोहन भागवत के सामने बैठकर उन समस्याओं पर चर्चा करें जो कि इन दिनों मुसलमानों को पेश आ रही हैं, जिन्हें पैदा करने में संघ के संगठनों का ही हाथ है। आज पूरे देश में मुसलमानों को भीड़ की हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है और साथ ही मुसलमानों को यह भी उपदेश दिया जा रहा है कि वे अपने अतिवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करें। पिछले दिनों मुंबई के एक पांच सितारा होटल में जमा हुए कुछ मुसलमानों को मोहन भागवत ने यही सबक पढ़ाया था। इससे पूर्व गाजियाबाद में भी एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों को यही सबक पढ़ाया था। हैरानी की बात यह है कि मुंबई में हुई बैठक में किसी भी मुसलमान को यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि मोहन भागवत हिंदू समाज में पनप रहे अतिवाद को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? जहां तक इस्लाम का सवाल है यह तो रसूल के जीवन काल में ही भारत पहुंच गया था। रसूल अल्लाह के सहयोगी मलिक बिन दीनार भारत में आने वाले पहले मुसलमान थे और यहीं हिंदुस्तान की पहली मस्जिद का निर्माण हुआ जो आज भी मौजूद है। मुसलमान बादशाह तो इससे 500 वर्ष बाद भारत आए। यह हकीकत है कि मुसलमान बादशाहों ने लगभग आठ सौ वर्षों तक इस देश पर हुकूमत की। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने जबरन इस्लाम का प्रचार किया हो। सच्चाई तो यह है कि भारत में हिंदू समाज के छुआछूत के कारण लोग मुसलमान बने। इस्लाम का प्रचार सूफियों ने किया जो कि एकता और भाईचारे में विश्वास रखते थे। यही कारण है कि आज भी उनकी दरगाहों में हाजिरी देने वालों में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू होते हैं। मुसलमान अपने देश के तौर पर हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और ऐसा करना इस्लामिक शिक्षा का एक अंग है। हालांकि देश को पवित्र मानकर उसकी पूजा करना इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं है।

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक

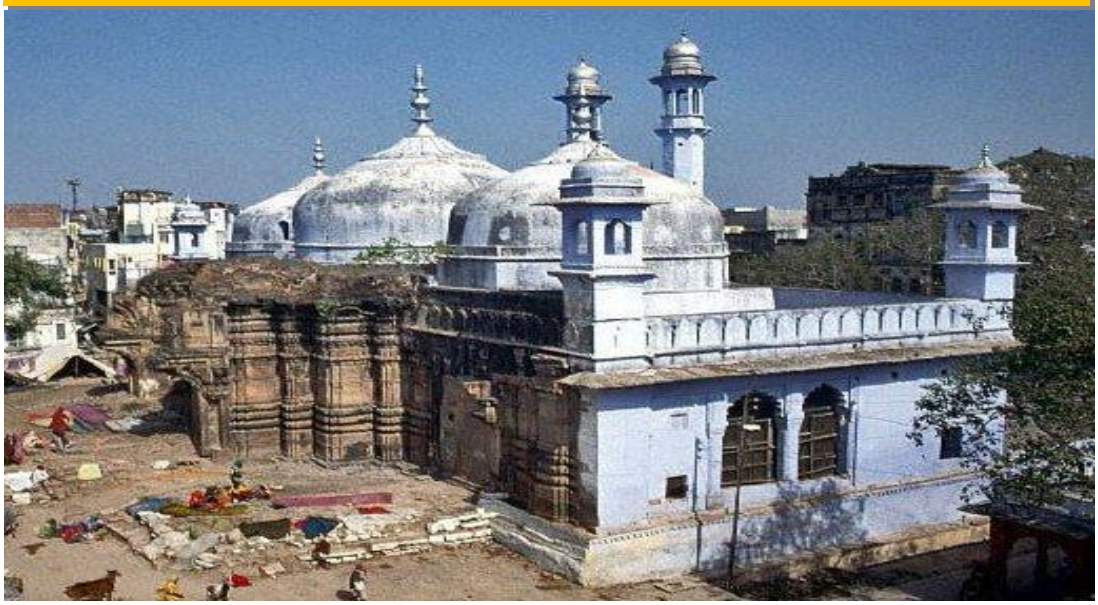

इंकलाब (10 सितंबर) के अनुसार वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद ने एक नया मोड़ लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही निचली अदालत ने इस मामले की सुनवाई भी रोक दी है। उच्च न्यायालय ने भारत सरकार सहित सभी हिंदू पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर जवाबदावा दायर करने की हिदायत दी है और अगली सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। उच्च न्यायालय ने यह फैसला उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद की इतेजामिया कमेटी की याचिकाओं पर सुनाया है, जिन्होंने सिविल कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। वक्फ बोर्ड और मस्जिद प्रबंधक कमेटी ने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए इसे इंसाफ की जीत की संज्ञा दी है।

वाराणसी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश आशुतोष तिवारी ने 8 अप्रैल 2021 को यह आदेश जारी किया था कि भारत सरकार का पुरातत्व विभाग मस्जिद परिसर का सर्वे करवाएगा और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। सर्वे की संपूर्ण फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाने का भी निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय का कहना है कि सिविल जज को ऐसे मामलों में फैसला सुनाने का अधिकार ही नहीं है, जिससे संबंधित उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या संसद ने पहले से ही कोई कानून बना रखा हो। दोनों मुस्लिम संगठनों ने सिविल जज के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी थी कि संसद द्वारा पारित किए गए 1991 के कानून के तहत बाबरी मस्जिद को छोड़कर देश की किसी भी धार्मिक उपासना स्थल पर दूसरे धर्म की दावेदारी को नहीं माना जाएगा। अर्थात आजादी तक जिस उपासना स्थल पर जिस भी संप्रदाय का अधिकार था उसे ही बरकरार रखा जाएगा। इस कानून के कारण ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

15 अक्टूबर 1991 को हिंदुओं ने सिविल कोर्ट वाराणसी में यह मुकदमा दायर किया था कि जिस स्थान पर नमाज अदा की जा रही है वह हिंदुओं का है। क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदुओं का दावा था कि यह स्वयंभु विश्वेश्वरनाथ का मंदिर है और

पूरा स्थान उनका है। मुसलमानों का यह दावा है कि वे इस स्थान पर आजादी से सैकड़ों वर्ष पूर्व से नमाज अदा कर रहे हैं।

टिप्पणी : मुस्लिम इतिहासकार फिरिश्ता ने दावा किया है कि महमूद गजनवी ने भारत में सैकड़ों मंदिरों को तबाह किया और उनकी अकूत संपदा को लूटा और लाखों लोगों को गुलाम बनाकर ले गया। मंदिरों को हर मुस्लिम आक्रमणकारी ने अपना निशाना बनाया। उन्हें लूटा, मूर्तियों को तोड़ा और अनेक मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया। सन मार्टिन ने अपनी पुस्तक में पुरातत्व प्रमाण प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया है कि औरंगजेब ने इस देश में सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया और उन्हें मस्जिदों में बदला। इनमें विश्वविख्यात काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। 1664 में औरंगजेब ने इस मंदिर पर पहला हमला किया था जिसे नागा साधुओं ने हजारों की संख्या में आत्मबलिदान देकर विफल कर दिया। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ की पवित्र मंदिर को ध्वस्त करके उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। वाराणसी विश्व के प्राचीनतम नगरों में से है। काशी विश्वनाथ हिंदुओं के परम पवित्र बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं।

अनेक विदेशी इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद के समीप प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरावशेष दबे हुए हैं। इतिहासकारों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में सर्वप्रथम काशी विश्वनाथ के पवित्र मंदिर को ध्वस्त किया। मगर इस मंदिर का पुनर्निर्माण 13वीं शताब्दी में कुछ गुजराती व्यापारियों ने किया, जिसे बाद में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने पुनः मिट्टी में मिला दिया। 15वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी की फौज ने फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया, जिसका नवनिर्माण अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने करवाया। इसी मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया था।

वर्तमान मंदिर जो कि पुराने मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है उसका निर्माण इंदौर की महाराणी अहिल्या बाई होल्कर ने करवाया था। बताया जाता है कि उनके ससुर मलहार राव होल्कर ने 1742 में इस बात का प्रयास किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त करके वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाए। मगर अवध के नवाबों के हस्तक्षेप के कारण यह संभव नहीं हो सका। अहिल्या बाई होल्कर ने वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 में करवाया था। यह मंदिर विश्वनाथ के मूल मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से कुछ दूरी पर स्थित है। इसी मंदिर को पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने 40 मन सोना दान दिया था जो कि आज भी इस मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ा रहा है। ■

उत्तर प्रदेश चुनाव हेतु ओवैसी की भागदौड़

उत्तर प्रदेश के आने वाले विधान सभा चुनावों में भाग लेने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतिहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य का चुनावी दौरा शुरू कर दिया है।

इंकलाब (8 सितंबर) के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेंस में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को अपना निशाना बनाया और कहा कि ये दोनों मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं मगर सत्ता में हिस्सेदारी के प्रश्न पर इनको हिंदू-मुस्लिम भाईचारा खतरे में नजर आता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम अतीक अहमद को भी अपना सदस्य बना

रहे हैं। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप अपराधी तत्वों को अपनो पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि उत्तर पदेश में भाजपा के 17 प्रतिशत विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड है और इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके राज में ही मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और अगर वे दंगाईयों के खिलाफ कार्रवाई करते तो भाजपा को सत्ता में आने के बाद इन दंगों के 77 दोषियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने मुलायम सिंह और मायावती को भरपूर वोट दिए मगर इसके बदले में उन्हें क्या हासिल हुआ? जब आजम खान झूठे मुकदमो में फंसाए गए तो क्या उनके पक्ष में समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई थी? उन्होंने कहा कि मैने राजनीति में कदम सिर्फ मुसलमानों को उनका उचित अधिकार दिलाने के लिए रखा है।

इंकलाब (6 सितंबर) के अनसार ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में 100 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की घोषणा की है। मजलिस की राज्य ईकाई के अध्यक्ष शौकत अली ने दावा किया कि अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में ओवैसी को राज्य में एक भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी थी। यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने ओवैसी को चुनाव अभियान शुरू करने की अनुमति दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक बार ओवैसी को रैली करने की दी गई अनुमति को निश्चित समय पर रद्द कर दिया गया।

इंकलाब (14 सितंबर) के अनुसार कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'अब्बा जान' वाले बयान का उल्लेख करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर बाबाजी ने मुसलमानों के लिए कोई काम किया होता तो उन्हें 'अब्बा अब्बा' न चिल्लाना पड़ता। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह ह कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने 162 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को दिए थे, जिसमें से योगी सरकार ने सिर्फ 16 करोड़ रुपये ही खर्च किए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सिर्फ आठ मुसलमानों को ही मकान मिले हं।

इंकलाब (11 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भारी धक्का लग सकता है। क्योंकि मजलिस के अध्यक्ष असदुद्दीन

ओवैसी ने पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद अब बसपा के सांसद मुख्तार अंसारी और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान को भी अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए गतिविधियां तेज कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वे मुख्तार अंसारी को इस बार अपना टिकट नहीं देंगी। क्योंकि वह माफिया है। इस घोषणा के बाद मजलिस ने मुख्तार अंसारी से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में हाल ही में मजलिस के कुछ नेताओं ने रामपुर से सांसद आजम खान से भी मुलाकात की थी। आजम खान इन दिनों समाजवादी पार्टी से सख्त नाराज हैं। इसलिए उन्हें और उनकी पत्नी तजीन फातिमा को कांग्रेस और मजलिस दोनों अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने भी रामपुर जाकर आजम खान के परिवारजनों से बातचीत की थी। जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम चेहरे मजलिस में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का नक्शा ही बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात 20 प्रतिशत है और कुल 403 सीटों में से 145 सीट एसी हैं जहां विजय की कुंजी मुसलमानों के हाथों में है। ओवैसी का यह भी प्रयास है कि कुछ दलित और पिछड़े गैर मुस्लिम नेताओं को मजलिस में शामिल किया जाए।

इत्तेमाद (1 सितंबर) के अनुसार ओवैसी ने गुलबर्गा में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य देश की राजनीति में मुसलमानों को उनका उचित हिस्सा दिलाना है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे देश भर में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए मुसलमानों और दलितों का एकजुट होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस राम-श्याम की जोड़ी हैं। ये दोनों मुसलमानों का भला नहीं चाहते। इसलिए इन दोनों को सत्ता से हटाना हमारा लक्ष्य है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (14 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि ओवैसी भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं और उन्होंने भाजपा को उत्तर प्रदेश में पुनः सत्ता में लाने के उद्देश्य से मुस्लिम मतों को विभाजित करने की योजना बनाई है। इसी लक्ष्य से उन्होंने 100 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। हमारा समाज के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में साम्प्रदायिक भावना भड़काने के आरोप में मजलिस के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राम स्नेही घाट पर स्थित मस्जिद के मामले पर जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अवांछनीय टिप्पणी की है। बाराबंकी की सिटी पुलिस ने ओवैसी के खिलाफ कोरोना नियमों का उल्लंघन करने और अवैध रूप से रैली आयोजित करने के मामले में केस दर्ज किया है। दरियाबाद के विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव से मुलाकात करके उनसे यह मांग की थी कि ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उनका आरोप है कि प्रशासन ने ओवैसी को सिर्फ 50 लोगों की बैठक को संबोधित करने की अनुमति दी थी। मगर उन्होंने सैकड़ों की भीड़ इक्ट्ठी कर दी। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव के निर्देश पर ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

अवधनामा ने 11 सितंबर के संपादकीय में कहा है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर उनका वोट प्राप्त

करने का प्रयास कर रहे हैं। जब से बिहार में इनकी पार्टी को पांच सीटें मिली हं और कुछ अन्य स्थानों पर स्थानीय निकायों में भी कामयाबी मिली है तब से उनके हौसले बढ़ गए हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि ओवैसी ने राज्य विधान सभा के चुनाव में 100 उम्मीदवार खड़े करने का जो निर्णय किया है उससे निश्चित रूप से भाजपा को लाभ होगा। क्योंकि मजलिस के उम्मीदवार मुसलमानों क मत बटोरकर अन्य विपक्षी दलों के हार का कारण बनेंगे, जिसका लाभ निश्चित रूप से भाजपा को होगा। ओवैसी उत्तर प्रदेश में किससे गठबंधन करेंगे यह अभी साफ नहीं है। क्योंकि अगर एसपी, बीएसपी या कांग्रेस उनसे हाथ मिलाएंगे तो उनको यह डर है कि उनका बचा खुचा हिंदू वोट भी खिसक जाएगा और वे कही के नहीं रहेंगे और अगर वे हाथ नहीं मिलाते तो जिन वोटों के आधार पर गैर भाजपाई उम्मीदवार जीतने की आशा करता है उसमें ओवैसी सेंध लगाकर विपक्षी दल का सारा खेल ही बिगाड़ देंगे। अगर मुख्तार अंसारी, आजम खान और अतीक अहमद का परिवार मजलिस का हाथ थाम लेता है तो उत्तर पदेश की राजनीति का रंग ही बदल जाएगा।

इंकलाब (8 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय लोकदल के नेता शाहिद सिद्दीकी ने कहा है कि ओवैसी भाजपा के लिए आशा की किरण हैं।

झारखंड विधान सभा में नमाज के लिए कमरा

इंकलाब (7 सितंबर) के अनुसार झारखंड विधान सभा के नए भवन में नमाज के लिए एक कमरा दिए जाने के मुद्दे पर भाजपा के विधायकों ने जबर्दस्त हंगामा किया और विधान सभा में ही भजन-कीर्तन शुरू कर दिया। भाजपा के विधायकों ने मांग की कि इस आवंटन को तुरंत रद्द कर दिया जाए। विधान सभा का अधिवेशन शुरू होते ही भाजपा के विधायकों ने हरे राम, हरे कृष्ण, हर हर महादेव और जय श्रीराम के नारे लगाने शुरू कर दिए। देवघर के विधायक तो पुजारी के वेष में ही सदन में पहुंचे थे। उन्होंने सदन में शंख बजाना शुरू कर दिया। भाजपा के विधायकों ने कहा कि उनका विरोध उस समय तक जारी रहेगा जब तक नमाज के लिए कमरे का आवंटन रद्द नहीं किया जाता।

झारखंड विधान सभा सचिवालय की ओर से विधान सभा की नयी इमारत में नमाज अदा करने के लिए एक कमरा आवंटित किया गया है। इस संबंध में विधान सभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने कहा कि अविभाजित बिहार के समय

से ही विधान सभा भवन में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटित करने की व्यवस्था रही है और झारखंड में भी इसी परंपरा का पालन किया जा रहा है। इसलिए इस प्रश्न पर सदन में हंगामा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीज़ल हसन ने कहा कि क्योंकि विधान सभा में नमाज पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए घर जाना पड़ता है, जिससे विधान सभा की कार्रवाई में व्यावधान पैदा होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की भूमिका को कौन नहीं जानता। इसलिए वह मामूली मामलों को उछालकर राजनीति खेल रही है। एक अन्य मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड विधान सभा के पुराने भवन में भी नमाज अदा करने के लिए एक कमरा था और यह व्यवस्था भाजपा सरकार के दौरान भी कायम रही थी। इसलिए भाजपा का विरोध बेबुनियाद है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का दावा है कि सन् 2000 में उस समय के विधान सभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी की सलाह पर नमाज के लिए एक कमरा आवंटित किया था। फुरकान अंसारी ने कहा कि किसी जगह नमाज अदा करने का यह हरगिज मतलब नहीं है कि वह जगह उपासना स्थल बन गया है।

झारखंड विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने कहा कि बिहार विधान सभा में मुसलमान विधायकों के नमाज अदा करने के लिए एक कमरे की व्यवस्था थी। यदि ऐसी व्यवस्था झारखंड में भी की गई है तो इसमें क्या बुराई है? झारखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि विधान सभा में नमाज के लिए एक कमरा आवंटित करने की व्यवस्था संयुक्त बिहार के समय से ही चली आ रही है। वहां भाजपा सत्ता में शामिल है। पहल वह वहां पर विधान सभा में आवंटित कमरे को रद्द क्यों नहीं करवाती?

सेक्युलरवादियों के निशाने पर संघ परिवार

कुछ वामपंथी बुद्धिजीवियों द्वारा संघ परिवार की तुलना तालिबान से करने के कारण देश की राजनीति में नया बवाल पैदा हो गया है।

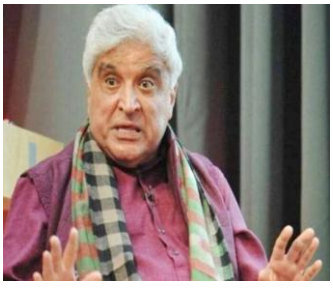

इंकलाब (4 सितंबर) के अनुसार मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने एक अंग्रेजी न्यूज चैनल पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों का लक्ष्य भी वही है जो तालिबान का है। हालांकि भारतीय संविधान संघ परिवार के रास्ते में बाधा पैदा कर रहा है मगर मौका दिया गया तो वे इस हद को पार करने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद कुछ मुसलमानों द्वारा खुशी मनाए जाने पर टिप्पणी करते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि दुनिया भर के दक्षिणपंथी एक हैं। भारत में भीड़ द्वारा अल्पसंख्यकों की पिटाई और हत्याओं की चर्चा करते हुए अख्तर ने कहा कि यह पूरी तरह से तालिबान बनने की फुल ड्रेस रिहर्सल है। ये तालिबान हरकतों को अपना रहे हैं। ये एक ही लोग हैं। बस नाम का फर्क है। उन्होंने कहा कि जो लोग संघ परिवार जैसे संगठनों का समर्थन करते हैं उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में सिर्फ मुट्ठी भर मुसलमान तालिबान के प्रशंसक हैं। ज्यादातर हिंदुस्तानी मुसलमान इसके विरोध में हैं।

इंकलाब (6 सितंबर) के अनुसार जावेद अख्तर के इस बयान के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है और कहा गया

है कि जावेद अख्तर ने जानबूझकर संघ परिवार का अपमान किया है। इसके बाद मुंबई स्थित जावेद अख्तर के आवास के बाहर संघ परिवार से संबंधित संगठनों ने प्रदर्शन भी किया।

इंकलाब (6 सितंबर) के अनुसार भाजपा के नेता राम कदम ने धमकी दी है कि अगर जावेद अख्तर माफी नहीं मांगते तो उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी।

इंकलाब (9 सितंबर) के अनुसार 100 से अधिक प्रमुख नागरिकों ने नशीरूद्दीन शाह और जावेद अख्तर के खिलाफ संघ परिवार द्वारा चलाए जा रहे अभियान की निंदा की है और इन दोनों को समर्थन देने की घोषणा की है। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में तीस्ता सीतलवाड़, आनंद पटवर्धन, जावेद आनंद, शबनम हासमी, जफर आगा जैसे लोग शामिल हैं।

इंकलाब (11 सितंबर) के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना अफगानिस्तान में काबिज तालिबान से की है और कहा है कि तालिबान और आरएसएस की सोच महिलाओं के बारे में एक जैसी है। जैसे तालिबान इस्लामिक स्टेट चाहते हैं उसी तरह से कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इन दोनों की मानसिकता एक जैसी है। इन लोगों की जितनी निंदा की जाए कम है। दिग्विजय सिंह के बयान पर टिप्पणी करते हुए मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को राष्ट्रवादियों को बदनाम करने की आदत है और उन्हें संघ से एलर्जी है। इसलिए उनकी बातों को कतई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

हमारा समाज (10 सितंबर) के बिहार के कांग्रेसी नेता तारिक अनवर भी इस विवाद में उलझ गए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस में यह बयान दिया था कि अफगानिस्तान के तालिबान और हमारे देश के आरएसएस की सोच एक जैसी है। इसके बाद बिहार की राजधानी पटना के शिवपुरी मोहल्ला के एक निवासी सोबीर कुमार ने पटना थान में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है कि तारिक अनवर का बयान गैरजिम्मेवाराना है और इससे भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं की भावना आहत हुई हैं। जब तारिक अनवर से इस एफआईआर पर टिप्पणी करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि अब मुकदमेबाजी द्वारा गांधीवादियों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। मगर हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम गांधी और नेहरू के अनुयायी हैं और इस देश और संविधान को बचाने के लिए और देश को फासीवाद की ओर जाने से रोकने के लिए हर तरह की कुर्बानी देंगे।

इत्तेमाद (7 सितंबर) के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी मंत्री और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा पुलिस ने बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया है। 81 वर्षीय अजीज कुरैशी रामपुर में आजम खान की पत्नी और परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए आए थे। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना शैतान से की थी। शिकायत करने वाले आकाश सक्सेना ने कहा है कि कुरैशी की टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदशक अविनाश चंद्र ने बताया कि डॉ. कुरैशी समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के परिवारजनों से मिलने के लिए रामपुर गए थे वहां उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए सीतापुर जेल में कैद आजम खान के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए यह टिप्पणी की थी। इस पर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। डॉ. कुरैशी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा था कि यह इंसान और शैतान की लड़ाई है। एक तरफ इंसान हैं और दूसरी तरफ शैतान हैं। ऐसे में सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। उन्होंने रामपुरवासियों से अपील की थी कि वे इस उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर उतरें।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में मतभेद

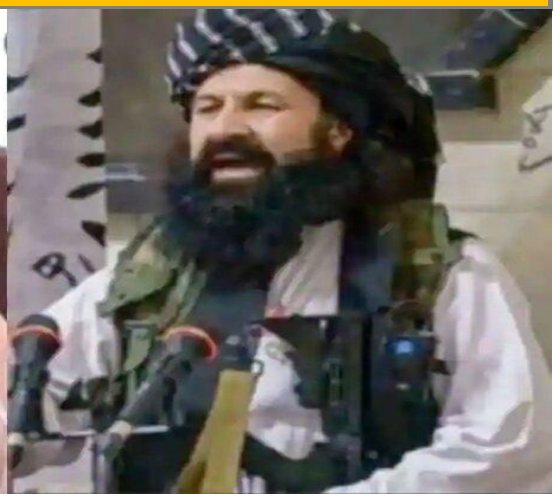

अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार बनी है, उसमें शामिल हुए विभिन्न गुटों में मतभेद पैदा होने की खबर है।

रोजनामा सहारा (16 सितंबर) के अनुसार हाल ही में तालिबान के दो प्रमुख नेताओं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और खलीलुर रहमान हक्कानी के बीच काफी गरमा-गरमी हुई है। इस संदर्भ में बीबीसी ने अपनी पश्तो सेवा में उल्लेख किया है। कहा जाता है कि तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री और एक अन्य मंत्री के बीच काबुल के महल में काफी गरमा-गरमी हुई है। हाल ही में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के निष्क्रिय हो जाने के कारण राजनीतिक क्षेत्रों में यह चर्चा गरम है कि तालिबान के नेताओं में गंभीर मतभेद हो गए हैं। हालांकि तालिबान ने इसका खंडन किया है। बताया जाता है कि यह झगड़ा गत सप्ताह हुआ था और बहस की शुरुआत तालिबान की नई सरकार के ढांचे से शुरू हुई। अब्दुल गनी बरादर वर्तमान व्यवस्था से खुश नहीं थे। इसके बाद उनका एक अन्य प्रमुख तालिबान नेता खलीक़ल रहमान हक्कानी से गरमा-गरमी हुई। कहा जाता है कि इसका कारण यह है कि ये दोनों गुट इस बात पर नाराज थे कि तालिबान की अफगान विजय का श्रेय लेने पर इन दोनों में विवाद पैदा हो गया था। मुल्ला बरादर का कहना था कि तालिबान को जो विजय प्राप्त हुई है उसका श्रेय उन जैसे नेताओं की डिप्लोमैटिक स्तर पर गतिविधियों से है। जबकि हक्कानी ग्रुप की राय थी कि तालिबान की विजय युद्ध के कारण हुई है। मुल्ला बरादर ऐसे पहले तालिबान नेता हैं जिन्होंने 2020 में अमेरिका के तात्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से सीधी बात की थी और अमेरिकी सेनाओं के अफगानिस्तान से निष्कासन के बारे में हुए समझौते पर तालिबान की ओर से हस्ताक्षर किए थे। दूसरी ओर हक्कानी नेटवर्क की भूमिका अफगानिस्तान में युद्ध पर केन्द्रित रही है। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान की अंतरिम सरकार में गृहमंत्री हैं। कहा जाता है कि काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए हमले में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अतिरिक्त कश्मीर में जो आतंकवादियों की गतिविधियां भारत के खिलाफ चल रही हैं उसमें भी उनका हाथ बताया जाता है। तालिबान का कहना है कि मुल्ला बरादर तालिबान के प्रमुख से विचार-विमर्श करने के लिए कंधार गए हैं। जबकि उन्होंने बीबीसी को बताया था कि वे

थक गए हैं इसलिए कुछ दिन आराम करना चाहते हैं। तालिबान क सवोर्च्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा भी अभी तक काबुल में नजर नहीं आए।

हमारा समाज (8 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी नई सरकार का ऐलान कर दिया है, जिसमें मोहम्मद हसन अखुंद सरकार के प्रमुख होंगे। जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री होंगे। नए मंत्रिमंडल की घोषणा तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने की। मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद को रक्षा मंत्रो और सिराजुद्दीन हक्कानी को गृहमंत्री नियुक्त किया गया है। जबकि मुल्ला हिदायतुल्लाह वित्त मंत्री और मुल्ला खैरूल्लाह सूचना मंत्री बनाए गए हैं। मौलवी अमीर खान मुत्तकी विदेश मंत्री, कारी दीन मोहम्मद अर्थव्यवस्था मंत्री बनाए गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार मौलवी नूर मोहम्मद साकिब हज व वक्फ मंत्री होंगे। मौलवी अब्दुल हकीम विधि मंत्री, नुरूल्लाह नूरी सीमावर्ती मामलों के मंत्री होंगे। युनूस अखुंदजादा को गुप्तचर विभाग का प्रमुख बनाया गया है। मुल्ला मोहम्मद ईस्सा अखुंद खनिज व पेट्रोलियम मंत्री नियुक्त किए गए हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलाना अब्दुल सलाम दोनों मौलाना मोहम्मद हसन अखुंद के सहायक होंगे। शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई को उप विदेश मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कारी फसीहुद्दीन को अफगान सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान अंतरिम सरकार की अवधि फिलहाल छह महीने होगी। बदलते हुए हालात को देखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। स्थाई सरकार में सभी गुटों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान में अब शांति है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मीडिया में यह प्रचार किया जा रहा है कि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध हैं। हालांकि हमारे मामले में पाकिस्तान किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। हमारे संघर्ष में हमें दुनिया भर का सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि पंजशीर का क्षेत्र भी पूर्ण रूप से अब हमारे नियंत्रण में है। हम किसी विशेष जाति या कबीले का प्रतिनिधित्व नहीं करते और सरकार में किसी भी विशेष कबीले का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

सियासत (8 सितंबर) के अनुसार तालिबान ने यह घोषणा की है कि अफगानिस्तान का नया संविधान कुरान और हदीस के अनुसार होगा और देश की शासन व्यवस्था शरिया के अनुसार चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार के फौजी हमारा साथ दें। हम किसी तरह का विरोध किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे और जो हमारे खिलाफ हथियार उठाएगा वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अफगानिस्तान का युद्ध समाप्त हो चुका है। यह समय शांति और पुनर्निर्माण का है। इसके लिए हमें जनता के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख जनरल फैज हमीद ने हाल ही में काबुल का दौरा किया था और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भेंट की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कुछ बातों की परेशानी ह जिसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि पंजशीर में उनके हाथ काफी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र लगे हैं जो कि विदेशियों ने वहां पहुंचाए थे। अफगानिस्तान में हम और युद्ध नहीं चाहते।

सियासत (3 सितंबर) के अनुसार तालिबान के दोहा स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहैल साहीन ने कहा कि तालिबान दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने के हकदार हैं। इसलिए हम कश्मीरी मुसलमानों के हक में भी आवाज

बुलंद करेंगे और उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी नीति किसी भो देश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने की नहीं है। मगर मुसलमान होने के नाते यह हमारा कर्तव्य और हक है कि हम कश्मीर, भारत और किसी भी देश में मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाएं और उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुरूप कश्मीर समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान ने जब भी प्रयास किए भारत ने उस पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय कश्मीर में मुसलमानों को दबाया जा रहा है और उनपर अत्याचार जारी हैं। अधिकृत जम्मू-कश्मीर में अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त करने की घोषणा करके सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया और वहां की जनता को बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया। सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद हैं और सारा जन-जीवन ठप है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने विवादित नागरिकता कानून लागू किया जिसके खिलाफ देश भर के मुसलमानों ने जबर्दस्त विरोध किया था। भारत सरकार ने इन्हें उत्पीड़न का निशाना बनाया और कई लोग मारे गए। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान की शासक पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के एक नेता ने यह बयान दिया है कि तालिबान हमारे साथ हैं और कश्मीर को मुक्त कराने में वे हमारा सहयोग देंगे।

अवधनामा (14 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पूरे देश में सह शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। छात्राओं को विश्वविद्यालय में अलग कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करनी होगी और उन्हें कोई पुरूष प्राध्यापक शिक्षा नहीं दे सकेंगे। इससे पूर्व भी 1996-2000 के बीच तालिबान ने महिलाओं की शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं को हिजाब पहनना होगा और चेहरे को ढकना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं बिना बुर्के के नहीं जा सकेंगी। उन्हें इस्लामिक लिबास पहनना होगा।

इंकलाब (10 सितंबर) के अनुसार तालिबान ने पूरे देश में प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लिबास पर तालिबान ने जो प्रतिबंध लगाया है उसके खिलाफ महिलाओं ने कई जगह पर प्रदर्शन किए हैं। इनको तितर-बितर करने के लिए तालिबान ने ताकत का भी इस्तेमाल किया है।

इंकलाब (16 सितंबर) के अनुसार सोशल मीडिया पर महिलाएं इन प्रतिबंधों का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि वे इन प्रतिबंधों को नहीं मानेंगी बल्कि अफगानिस्तान का परंपरागत लिबास पहनेंगी। एक महिला प्रोफेसर बहार जलाली ने कहा है कि तालिबान को हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। हम इसका विरोध करेंगे। काबुल विश्वविद्यालय में कक्षाएं शुरू हो गई हैं मगर उसमें भाग लेने के लिए आने वाली सभी महिलाओं ने बुर्के पहने हुए थे। जिन कमरों में महिलाओं की कक्षाएं लगाई गई हैं उनके बाहर भी काले रंग के पर्दे लगाए गए थे।

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला

रोजनामा सहारा (12 सितंबर) के अनुसार बलूचिस्तान में आजाद बलूचिस्तान के समर्थक इन दिनों काफी सक्रिय हैं। पाकिस्तान सरकार ने यह स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान के जिला केच के बलदा नामक क्षेत्र में सशस्त्र लोगों ने पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कोर के काफिले पर हमला किया, जिसमें दो पाकिस्तानी फौजी मारे गए। पाकिस्तानी सैनिकों ने आक्रमणकारियों पर जवाबी गोली चलाई मगर वे फरार होने में सफल हो गए। कलात में कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने पाकिस्तान पुलिस के एक वाहन पर बम फेका, जिसमें दो पुलिस वाले मारे गए और दो जख्मी हुए। बलूचिस्तान के गृहमंत्री मीर जिया उल्लाह लंगाऊ ने इन हमलों की निंदा की है और कहा है कि विद्रोही तत्वों को कुचल दिया जाएगा। हाल ही में आजाद बलूचिस्तान के समर्थकों की गतिविधियों में तेजी आई है। गत सप्ताह क्वेटा मस्तुंग सडक पर सोना खां थाने के पास आत्मघाती हमले में चार सैनिक मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेवारी प्रतिबंधित संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कुबूल की थी।

एक अन्य हमले में पाकिस्तानी सेना का एक कप्तान मारा गया था और दो सैनिक घायल हुए थे। गत महीने बलूचिस्तान के जिला ग्वादर में चीनी नागरिकों को ले जाने वाली एक बस पर हुए हमलों में दो लोग मारे गए और अनेक घायल हो गए। 15 अगस्त को बलूचिस्तान के जिला लोरलाई के समीप पाकिस्तानी सेना पर हमले में एक जवान मारा गया और मेजर सहित दो लोग जख्मी हा गए। आठ अगस्त को क्वेटा में जिन्ना रोड़ पर हुए एक धमाके में दो पुलिस वाले मारे गए और 12 घायल हुए।

यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान को दी करोड़ों की सहायता

इंकलाब (16 सितंबर) के अनुसार यूरोपीय यूनियन अकाल से निपटने के लिए अफगानिस्तान को दस करोड़ यूरो की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख ने कहा है कि विश्व के 27 देश अफगान नागरिकों के साथ हैं और हम मानवीय आधार पर अफगान नागरिकों की सहायता को जारी रखेंगे। इससे पूर्व यूरोपीय यूनियन ने तालिबान सरकार को मान्यता न देने की घोषणा की थी और अफगानिस्तान को दिए जाने वाली सहायता को रोक दिया था। दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, विल क्लिंटन और जॉर्ज बुश ने एक नया संगठन बनाया है जो कि अमेरिका में आबाद होने वाले अफगान

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सहायता करेगा। जॉर्ज बुश ने कहा है कि हम अफगान नागरिकों के साथ हैं और उन्हें हम अमेरिका में पुनर्वास के लिए पूरी सहायता देंगे।

इंकलाब (15 सितंबर) के अनुसार चीन ने अफगानिस्तान को डेढ़ करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। इस संदर्भ में अफगानिस्तान के सरकारी प्रवक्ता ने चीन के विशेष दूत से मुलाकात की थी। इससे पूर्व भी चीन तीन करोड़ दस लाख डॉलर की सहायता अफगानिस्तान को देने की घोषणा कर चुका ह।

एक अन्य समाचार के अनुसार चीन ने अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की तीन हजार से ज्यादा खुराकें देने की घोषणा की है और इसके साथ ही उन्हें 20 करोड़ युवान की दवाईयां भी सप्लाई की जाएगी।

मस्जिद में धमाके के आरोपी को 53 वर्ष की कैद

इंकलाब (15 सितंबर) के अनुसार अमेरिका में एक मस्जिद में धमाका करने के आरोप में अतिवादी मिलिशिया गुट के प्रमुख एमली क्लेयर को 53 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। यह धमाका 2017 में हुआ था। यह धमाका मिनेसोटा नगर में स्थित दारूल फारूक इस्लामिक सेंटर में किया गया था। जब यह धमाका किया गया तो उस समय लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन इस धमाके में कोई व्यक्ति मरा या घायल नहीं हुआ था। अदालत में सरकारी वकील ने बताया कि एमली क्लेयर ने पहले अपना एक ग्रुप बनाया था, जिसका नाम द 'व्हाइट रैबिट्स' था। उसने अपने इस ग्रुप में

कुछ अन्य लोगों को भी भर्ती किया। 5 अगस्त 2017 को एक ट्रक पर सवार होकर 800 किलोमीटर दूर एक इस्लामिक सेंटर पर पहुंचे और वहां पर पाइप से धमाका किया। इस धमाके का लक्ष्य मुसलमानों को भयभीत करना और उनमें असुरक्षा की भावना पैदा करना था जो कि अमेरिकी नीतियों के सरासर खिलाफ है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। धमाके के बाद एफबीआई ने इस आरोपी को दो अन्य साथियों सहित 2018 में गिरफ्तार किया था और 2020 में उसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया था।

पाकिस्तान में अध्यापकों के जींस–टीशर्ट पहनने पर प्रतिबंध

इंकलाब (10 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने पूरे देश में महिला और पुरुष अध्यापकों के जींस और टीशर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमाम स्टाफ को पढ़ते समय गाउन पहनना होगा और प्रयोगशालाओं में लैब कोट का इस्तेमाल करना होगा। इस आदेश में कहा गया है कि महिला अध्यापकों को सलवार कमीज पहननी होगी और दुपट्टा या शॉल ओढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें हिजाब पहनने का भी निर्देश दिया गया है। किसी भी महिला अध्यापिका को जींस और टाइट लिबास पहनने की अनुमति नहीं होगी। वह सिर्फ पांव में लोफर और पंप शू पहनेगी। उन्हें सैंडल या चप्पल पहनने की अनुमति नहीं होगी। सर्दियों में कोट, ब्लेजर के अतिरिक्त स्वेटर, जर्सी या कार्डिगन पहन सकती हैं। जहां तक पुरुषों का संबंध है उन्हें सलवार कमीज पहननी होगी। किसी मर्द को जींस और पैंट पहनने की अनुमति नहीं होगी। गर्मियों में वे आधी आस्तीनों वाली शर्ट पहन सकते हैं। मगर उन्हें टीशर्ट पहनने की अनुमति नहीं होगी।

इजरायली प्रधानमंत्री का मिस्र दौरा

रोजनामा सहारा (15 सितंबर) के अनुसार इजरायली इतिहास में पहली बार एक निर्वाचित प्रधानमंत्री ने मिस्र का दौरा किया है। समाचारपत्रों के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल-सीसी से मुलाकात की। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात शर्म अल-शेख में हुई है, जिनमें इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच शांति बहाल करने के बारे में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त मिस्री गप्तचर विभाग के प्रमुख अब्बास कामल और इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इयाल हुल्टा ने भी भाग लिया। अरब जगत में मिस्र ने कई दशकों की दुश्मनी के बाद 1979 में इजरायल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि मिस्र के इजरायल के साथ आर्थिक, डिप्लोमैटिक और सुरक्षात्मक संबंध हैं। मगर इसके साथ ही वह मुस्लिम आतंकवादी संगठन हमास आर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास के साथ भी संबंध बनाए हुए है। इजरायल ने मिस्र से अनुरोध किया है कि वह गाजा में शांति व्यवस्था बनाने के लिए फिलिस्तीनियों से वार्ता करे। उसके बदले में इजरायल फिलिस्तीनियों को वैकल्पिक स्थान देने के लिए तैयार ह।

हूतियों की गोलाबारी से सऊदी बंदरगाह को भारी नुकसान

हमारा समाज (13 सितंबर) के अनुसार यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और यमन के अनेक बंदरगाहों पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले का लक्ष्य सऊदी अरब और यमन में विदेशों से प्राप्त होने वाली अस्त्र-शस्त्र की सप्लाई को रोकना है। हूतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। सरकारी प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि अल-माखा बंदरगाह पर इस हमले से भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि विद्रोही यमन की सरकारी सेना के मुख्यालय को अपना

निशाना बनाना चाहते थे। मगर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। सरकारी सेनाओं ने हूतियों के दो हेलिकॉप्टरों को मार गिराया है। यह हमला 11 सितंबर को किया गया था। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि हूती एक आतंकी संगठन है जो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से भिन्न नहीं है। ईरान ने इन विद्रोहियों को सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि यमन को इस समय जबर्दस्त संकट का सामना करना पड़ रहा है। लाखों यमनी बेघर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष यमन में भीषण अकाल की चतावनी दी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमन की सहायता के लिए दुनिया के देशों से चार अरब डॉलर की सहायता देने की अपील की थी मगर उसमें से सिर्फ पौने दो अरब डॉलर ही जमा हो सके हैं। सऊदी अरब ने यमन से छोड़ा गया एक ड्रोन मार गिराया है। हूतियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी नगर खमीस को निशाना बनाने की कोशिश की थी। सऊदी अरब के एक प्रवक्ता ने कहा कि हूती गत कई महीनों से सऊदी अरब के दक्षिणी क्षेत्रों के अनेक स्थानों को अपना निशाना बना रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान की शह पर हूतियों ने सऊदी अरब पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। क्योंकि सऊदी अरब के सुरक्षा कवच ने इन मिसाइलों और ड्रोनों के हमलों को विफल बना दिया है।

ईरान वार्ता के लिए तैयार

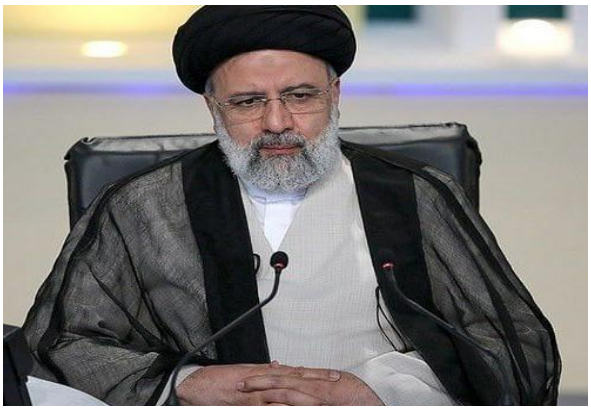

इत्तेमाद (6 सितंबर) के अनुसार ईरान ने परमाणु समझौतों के बारे में वार्ता शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की है। मगर यह भी कहा है कि यह वार्ता पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों और दबाव के तहत नहीं होनी चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी सरकार जरूर वार्ता करेगी। मगर यह किसी दबाव के तहत नहीं होनी चाहिए। अगर पश्चिमी देश हमारे खिलाफ दबाव जारी रखते हैं तो यह वार्ता सफल नहीं होगी। ईरान ने 2015 में अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को कम करने और यूरेनियम के भंडारों में कटौती करना था। इसके बदले में पश्चिमी देशों को ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करना था।

नए राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि हम अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क हैं मगर हमें अपन पड़ोसी देशों की सुरक्षा की भी उतनी ही चिंता है। अब तक हम 50 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों से इस संबंध में बातचीत कर चुके हैं। अफगानिस्तान के मामले की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की समस्या का हल वहां की जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए और वहां की सरकार जनता के वोटों से निर्वाचित होनी चाहिए। ईरान प्रारंभ से ही अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का इच्छुक रहा है। गत कई दशकों से अफगानिस्तान की जनता को युद्ध जैसे हालात का सामना करना पड़ा है। रईसी ने कहा कि हम किसी दबाव पर नहीं झुकेंगे। पश्चिमी देश हम पर बार-बार दबाव डालकर उसका नतीजा देख चुके हैं। हमने जो स्टैंड लिया है उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे।

सऊदी अरब में सिनेमाघर

इंकलाब (13 सितंबर) के अनुसार सऊदी अरब में गत चार वर्ष में 44 सिनेमाघर खुल चुके हैं। 'उर्दू न्यूज' की सूचना के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने यह स्वीकार किया है कि पहला सिनेमाघर 18 अप्रैल 2018 को रियाद में खोला गया था। जबकि हाल ही में दो सिनेमाघर रियाद और तैफ में खोले गए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब में 2018 से लेकर 2021 के दौरान प्रत्येक वर्ष दस सिनेमाघर खोले गए। सैकड़ों वर्षों से सऊदी अरब में सिनेमाघर खोलने पर प्रतिबंध था जिसे वर्तमान युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने उदारीकरण कार्यक्रम के तहत हटाने की घोषणा की थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अरब के 13 सूबों में से नौ में सिनेमाघर

खुल चुके हैं। इनमें से 21 रियाद में, 9 मक्का में और 8 पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। ये सिनेमाघर नौ कंपनियों ने खोले हैं। 2019 में सिनेमाघरों की संख्या 12 थीं जो कि अब बढ़कर 44 हो गई हैं। सऊदी अरब में पहला सिनेमाघर एक अमेरिकी कंपनी ने खोला है।

इस्लामिक स्टेट के हमले में 13 इराकी पुलिसकर्मी मरे

इंकलाब (6 सितंबर) के अनुसार इराक के उत्तरी भाग में पुलिस चौकी पर इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए हमले में कम-से-कम 13 पुलिसकर्मी मारे गए। इराकी सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी इराक में एक पुलिस चौकी पर कुछ सशस्त्र व्यक्तियों ने हमला किया था। इसके बाद सारे क्षेत्र में झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। इस हमले की जिम्मेवारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस हमले की शुरुआत किरकुक नगर के समीप एक चौकी पर हमले से हुई थी, जिसमें पांच सरकारी अधिकारी जख्मी हुए। प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस हमले में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद इस्लामिक स्टेट ने राशिद गांव के समीप पुलिस चौकी पर हमले शुरू कर दिए, जिनमें पुलिस के तीन वाहन तबाह हो गए। 2017 में इस क्षेत्र को इस्लामिक स्टेट के सैनिकों से अमेरिका ने मुक्त करवाया था। इसके बाद चार वर्ष तक इस क्षेत्र में शांति

रही। मगर अब फिर इस्लामिक स्टेट सक्रिय हो गया है। इस वर्ष के जुलाई महीने में इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कादिमी ने घोषणा की थी कि उनके देश को इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने के लिए अब अमेरिकी सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वे इराक से वापस जा सकते हैं। उनकी इस घोषणा के बाद ही इस्लामिक स्टेट के हमलों में तेजी आई है। ताजा समाचारों के अनुसार अमेरिका ने सीरिया की सीमा पर हवाई हमले किए हैं ताकि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को हमल करने से रोका जा सके।

अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न संस्थानों में पदाधिकारी नियुक्त

रोजनामा सहारा (10 सितंबर) के अनुसार भारत सरकार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें पूर्व अध्यक्ष सैयद गयोरुल हसन की जगह नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल मई 2020 में ही पूरा हो चुका था और इस समय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया था कि 31 जुलाई तक अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कर दे मगर अभी तक पांच सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इन सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र ही कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन और संसद के अधिवेशनों में व्यस्त होने के कारण नियुक्तियों में देर हुई है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न संस्थानों के अध्यक्षों और सदस्यों को मनोनीत करने की घोषणा की है। इन संस्थानों में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, उत्तर प्रदेश हज कमेटो, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश मदरसा तालिमी बोर्ड शामिल हैं। इन संस्थानों के पद कई वर्षों से खाली पड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का चेयरमैन गोरखपुर के चौधरी कैफ-उल-वारा को नियुक्त किया गया है। हज कमेटी का चेयरमैन मोहसिन रजा को बनाया गया है। जबकि फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ने सैयद अतहर जहीर जैदी को चेयरमैन बनया गया है। मदरसा तालिमी बोर्ड का चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद को बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चार सदस्यों को मनोनीत किया गया है। उर्दू अकादमी में अध्यक्ष क अतिरिक्त सैयद नदीम अख्तर (बुलंदशहर), सैयद इतरत हुसैन (वाराणसी), मोहम्मद आजाद अंसारी (सहारनपुर), डॉ. तलत सिद्दीकी (कानपुर) सलीम बेग (कानपुर) राजा कासिम (बाराबंकी), डॉ. शादाब आलम (लखनऊ), नवाब कम्बर

कैसर (लखनऊ), डॉ. रिजवाना (लखनऊ), मीशम जैदी (नोएडा), हाजी जहीर अहमद (मुरादाबाद), मोहम्मद इस्लाम सुल्तानी (बरेली) शामिल हैं।

हज कमेटी में अध्यक्ष मोहसिन रजा के अतिरिक्त असलम राईनी (मेरठ) शौकत अली (मेरठ), फैजल अली और सैयद कल्बे हुसैन (लखनऊ), मालाना हाफिज मोहम्मद जावेद (झांसी), मौलाना वकार हैदर (आजमगढ़), सरफराज अली (नोएडा), मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन (गोरखपुर), सैयद एहतेशाम अल हुदा (बरेली), सरवर सिद्दीकी (भदोही), अमानुल्लाह (मिर्जापुर), हाजी अब्दुल रहीम (वाराणसी), वसीम अहमद (प्रयागराज) शामिल हैं। फखरूद्दीन अली मेमोरियल कमेटी में डॉ. जहांआरा (प्रयागराज), मोहम्मद अनवर (सहारनपुर), तारिक सिद्दीकी (कासगंज), डॉ. शम्स परवेज (देवरिया) शामिल हैं। जबकि मदरसा तालिमी बोर्ड में कमर अली (लखनऊ), तनवीर रिजवी (सिद्धार्थ नगर), डॉ. इमरान अहमद (बिजनौर), असद हुसैन (हरदोई) शामिल हैं।

शिया बोर्ड के सदस्यों में मोहम्मद जरयाब जमाल (अमरोहा), सैयद शबाहत हुसैन रिजवी (सिद्धार्थ नगर), सैयद हसन कौसर और मौलाना रजा हुसैन (लखनऊ) शामिल हैं।

अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न संस्थानों में पदाधिकारियों के मनानयन पर टिप्पणी करते हुए **इंकलाब** (11 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इन सभी कमेटियों में ऐसे ही लोगों को जगह मिली है जो आरएसएस या भाजपा के समर्थक माने जाते हैं। मगर हज कमेटी में बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक को भी नियुक्त किया गया है। भाजपा में अब भी अधिकांश मुसलमानों की बेहद कमी है। इसलिए जिन लोगों को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है उनमें से किसी की भी अल्पसंख्यकों या राजनीति में कोई पहचान अभी तक नहीं है। हज कमेटी के नियमों के अनुसार कमेटी में कम-से-कम तीन मुस्लिम उलेमा होने चाहिए जिनमं से दो सुन्नी और एक शिया हो। मगर अभी तक यह उम्मीद भी पूरी नहीं हुई है। इसी तरह से किसी महिला को भी मनोनीत नहीं किया गया है। हालांकि यह जरूरी था कि महिला हज यात्रियों की समस्या पर विचार करने के लिए किसी महिला को मनोनीत किया जाता। काफी समय से शिया वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों की कुर्सियां खाली पड़ी हुई थीं। फिलहाल चार सदस्यों का मनोनयन हुआ है। मगर तीन सीटें अब भी खाली हैं।

सबसे हैरानी की बात यह है कि उर्दू अकादमी और फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी में जिन लोगों को इनका अध्यक्ष मनोनीत किया गया है उनका उर्दू साहित्य से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। इसलिए इस बात की आशा करना फिजूल है कि वे अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभा पाएंगे। वैसे इन सभी मनोनयन को आने वाले विधान सभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए यह आशा करना ही फिजूल है कि सरकार की अल्पसंख्यकों के कल्याण में किसी तरह की रुचि है। समाचारपत्रों में यह चर्चा रही है कि भाजपा और आरएसएस 2022 के चुनाव से पूर्व मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की कोई खास रणनीति अपना रहे हैं। मगर जब कोई सरकार साढ़े चार वर्ष तक सोई रहे और चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की कमेटियां बना दे तो इस तरह का प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

मदरसों को सहायता देने पर सवाल

अवधनामा (3 सितंबर) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सेक्युलर सरकार की ओर से धार्मिक संस्थानों को आर्थिक सहायता देने के बारे में सवाल उठाया है। उच्च न्यायालय ने पूछा है कि क्या एक सेक्युलर सरकार मदरसों को आर्थिक सहायता दे सकती है? क्या संविधान के

तहत मदरसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? उच्च न्यायालय ने यह भी पूछा है कि क्या महिलाओं को मदरसों में प्रवेश मिलता है? अगर नहीं तो क्या यह भेदभाव नहीं है? जो कि भारत के संविधान के खिलाफ है। उच्च न्यायालय ने यह भी पूछा है कि क्या इन मदरसों में सभी धर्मों की शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था है? उच्च न्यायालय ने यह प्रश्न मदरसा अंजुमन इस्लामिया द्वारा दायर की गई याचिका पर पूछा था। यह मदरसा बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त है और उसे राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। प्रबंध समिति ने यह शिकायत की थी कि उन्हें राज्य सरकार की यह सहायता दो वर्ष से प्राप्त नहीं हुई है।

निकाह को आसान बनाने की मांग

सियासत (9 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि वे विवाह आदि रस्मो पर अंधाधुंध धन खर्च न करें क्योंकि दौलत की नुमाइश करना इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए निकाह शरियत के अनुसार मस्जिदों में होने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रब्बै हसनी नदवी ने सामाजिक सुधारों की कमेटी की बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों में दहेज और दावत पर जो अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है वह शरा के अनुसार गलत है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। क्योंकि इससे समाज में मुसलमानों की गलत तस्वीर उभरती है। बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा कि मुसलमानों को इस तरह के समारोह पर अंधाधुंध धनराशि जुटाने की बजाय उसे शिक्षा और गरीबों की सहायता आदि मुद्दों पर खर्च करनी चाहिए। जकात फाउंडेशन के जफर महमूद ने कहा कि शादी से पूर्व इस बात का प्रयास होना चाहिए कि शादी या बारात में कम-से-कम लोगों को मेहमान के तौर पर बुलाया जाए। बोर्ड के सदस्य एस. क्यू. इल्यास ने कहा कि जो मुसलमान अपनी मनमानी करता है उसका निकाह उलेमा को नहीं पढ़ाना चाहिए।

वसीम रिजवी के खिलाफ याचिका खारिज

मुंबई उर्दू न्यूज (9 सितंबर) के अनुसार विवादित शिया नेता वसीम रिजवी के खिलाफ रजा अकेडमी ने लखनऊ उच्च न्यायालय में जो जनहित याचिका दायर की थी उसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश का कहना है कि इस मामले में आम जनता से कोई चर्चा नहीं की गई। देश भर में विभिन्न नगरों में वसीम रिजवो के खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं। वसीम रिजवी ने कुरान से 26 विवादित आयतों को निकालने की मांग की थी। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी इस याचिका को रद्द करके उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इससे पूर्व उन्होंने हजरत मोहम्मद की पत्नी हजरत आयशा के बारे में भी एक फिल्म बनाने की घोषणा की थी जिसका मुसलमानों ने जबर्दस्त विरोध किया था। लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा वसीम रिजवी से संबंधित जनहित याचिका पर टिप्पणी करते हुए रजा अकेडमी के महामंत्री मोहम्मद सईद नूरी ने कहा है कि हम उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगे। हमें आशा है कि हमें वहां से जरूर इंसाफ मिलेगा।

तब्लीगी मरकज को बंद रखा जाएगा

मुंबई उर्दू न्यूज (14 सितंबर) के अनुसार केन्द्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में शपथपत्र दाखिल करके तब्लीगी जमात के मुख्यालय को बंद रखने को उचित ठहराया है और कहा है कि हजरत निजामुद्दीन में स्थित इस भवन में विदेशियों के प्रवास के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक परेशानियां पैदा हो सकती हैं। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने इस केन्द्र को 31 मार्च 2020 को बंद कर दिया था और यहां पर लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिस समय इसे बंद किया गया उस समय वहां पर 1300 विदेशी रह रहे थे। इसलिए इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 310 के तहत बंद किया गया था। शपथपत्र में कहा गया है कि जहां तक धार्मिक आजादी का संबंध है सरकार ने सीमित संख्या में लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी है इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं हुआ है। इससे पूर्व दिल्ली उच्च

न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया था कि इस केन्द्र के आवासीय क्षेत्र को तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की मां के हवाले कर दिया जाए। लेकिन तब्लीगी जमात की गतिविधियां जिस क्षेत्र से चलती थी अभी वह बंद है। मौलाना साद की मां को यह निर्देश दिया गया है कि अगर वह चाहें तो वह इस केन्द्र के आवासीय क्षेत्र में निवास कर सकती हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

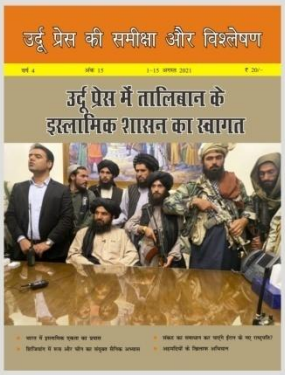

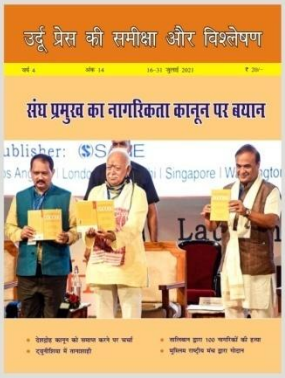

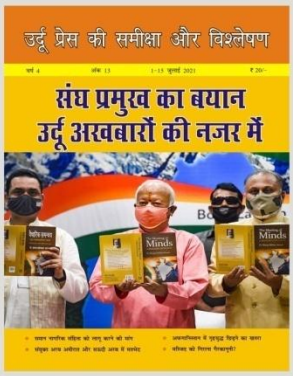

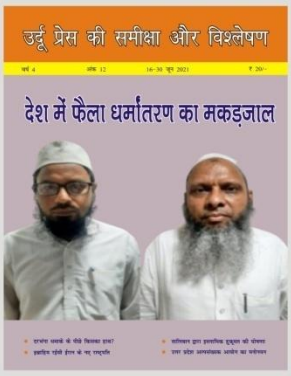

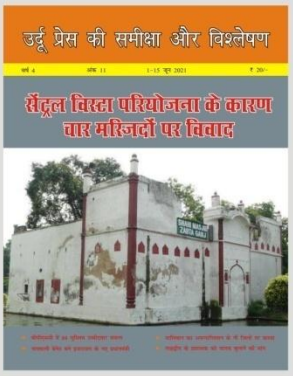

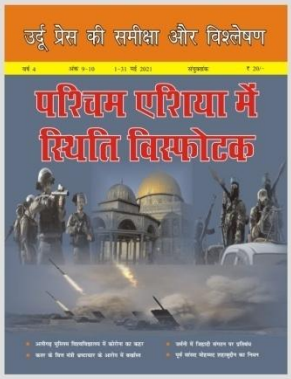

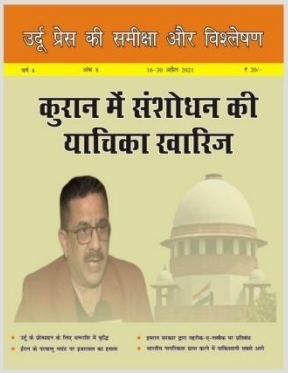

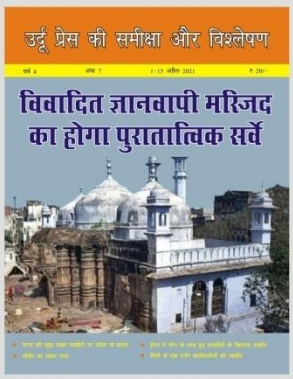

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in